



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, बुधस्पर्धिवार, जुलाई 31, 2003/श्रावण 9, 1925

No. 185]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2003/SRAVANA 9, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत (निर्णायक समीक्षा) सम्बन्धी अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2003

विषय : जापान, कोरिया गणराज्य तथा अमरीका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़ (एसबीआर) 1900 श्रृंखला के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा शुरू करना।

फा. सं० 15/5/2003-डीजीएडी.—सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (एतदपश्चात् निर्दिष्ट प्राधिकारी कहा जाएगा) ने दिनांक 3 जुलाई, 2001 की राजपत्र अधिसूचना सं. 34/1/2002-डीजीएडी के द्वारा अधिसूचित समीक्षा जांचों में अनंतिम जांच परिणामों में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत सीमाशुल्क उप-शीर्ष 3903.90 और 4002.19 के अंतर्गत वर्गीकृत जापान, कोरिया गणराज्य, अमरीका, ताइवान तथा टर्की मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़ (एसबीआर) 1900 श्रृंखला के सभी ग्रेडों के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी।

1. **शामिल उत्पाद:-** विचाराधीन उत्पाद जापान, कोरिया गणराज्य तथा अमरीका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क शीर्ष संख्या 3903.90 और 4002.19 के तहत वर्गीकृत स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़ (एसबीआर) 1900 श्रृंखला के सभी ग्रेड हैं। मूल जांच दिनांक 2/6/99 की अधिसूचना द्वारा की गई थी जिसमें एसबीआर 1500, 1700 और 1900 श्रृंखला पर शुल्क की सिफारिश की गई थी। तथापि दिनांक 3 जुलाई, 2001 की मध्यावधि समीक्षा अधिसूचना के द्वारा शुल्क का क्षेत्र एसबीआर 1900 श्रृंखला तक सीमित कर दिया गया था।

तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से मौजूदा निर्णायक समीक्षा जांचों के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

2. **जांच की शुरुआत:-** सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्राधिकारी को समय-समय पर इस बात की समीक्षा करनी होती है कि क्या लगाए

गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत है। प्राधिकारी ने जापान, कोरिया गणराज्य, अमरीका, ताइवान तथा टर्की मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500, 1700 और 1900 श्रृंखला में भिन्न-भिन्न ग्रेडों के एसबीआर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू की है (आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन और मै0 ऋषिरूप पोलीमर्स प्रा0 लि0, मुम्बई द्वारा समीक्षा के लिए अनुरोध के आधार पर) जैसा कि प्राधिकारी द्वारा 2-6-1999 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं0 30/1/97-एडीडी के द्वारा सिफारिश की गई थी और दिनांक 3 जुलाई, 2001 के अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं0 34/1/2000-डीजीएडी द्वारा एसबीआर 1900 श्रृंखला पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने को उचित माना था। निर्दिष्ट प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि, सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क) के उपबंधों के तहत इस चरण पर उपयुक्त रहेगी। घरेलू उद्योग ने एक याचिका दायर की है जिसमें जापान, कोरिया गणराज्य और अमरीका मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसबीआर पर पाटनरोधी शुल्क को आगे और 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने का अनुरोध किया है।

3. **प्रक्रिया:-** दिनांक 3 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं0 34/1/2000-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित मध्यावधि समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा जापान, कोरिया गणराज्य और अमरीका मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसबीआर के आयातों पर सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हैं।

4. इस समीक्षा में दिनांक 3 जुलाई, 2001 के अंतिम जांच परिणामों (समीक्षा) संबंधी अधिसूचना संख्या 34/1/2000-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

5. **जांच की अवधि:-** वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 (12 महीने) तक की है।

6. पूर्ववर्ती अधिसूचना में मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0, अपार हाउस, कारपोरेट पार्क, सियोल ट्राम्बे रोड, चैबूर, मुम्बई - 400071 तथा मै0 एपकोटैक्स लैटिसिस को घरेलू उद्योग माना गया था। प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार इन कंपनियों को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने का प्रस्ताव करते हैं।

7. **सूचना प्रस्तुत करना:-** सम्बद्ध देशों के निर्यातकों और भारत के आयातकों, जिन्हें इससे सम्बन्धित माना गया है तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करें और अपने विचार निम्न पते पर प्रस्तुत करें-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य मंत्रालय

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

8. **समय सीमा:-** वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी भी स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उत्तर देने के लिए निर्धारित समय सीमा में विस्तार नहीं करेंगे। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणामों को रिकार्ड कर सकते हैं।

9. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:-** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

10. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत:-** उपरोक्त पैरा के मद्दे नजर निर्दिष्ट प्राधिकारी सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए पाटनरोधी (निर्णायक समीक्षा) जांच शुरु करते हैं।

11. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना देने से मना करता है या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION (SUNSET REVIEW) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2003

Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on import of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series originating in or exported from Japan, Korea RP and USA.

F. No. 15/5/2003-DGAD.—The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 recommended continuation of the definitive Anti-Dumping duty in force on imports of all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series originating in or exported from Japan, Korea RP, USA, Taiwan and Turkey classified under customs sub-heading 3903.90 and 4002.19 of the Customs Tariff Act, 1975 in the Final Findings of review investigations notified vide Gazette Notification No. 34/1/2000-DGAD dated 3rd July, 2001.

1. Product Involved: The product under investigation is all grades of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1900 series classified under customs heading nos. 3903.90 and 4002.19 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Japan, Korea RP and USA. The original investigation concluded vide notification dated 2/6/99 recommended duty on SBR 1500, 1700 & 1900 series. However, scope of duty was restricted to SBR 1900 series vide mid term review notification dated 3rd July 2001.

The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present sunset review investigations.

2. Initiation:- The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made thereunder require the Authority to review from time to time, the need for continuance of Anti-Dumping duty. The Authority vide notification No. 34/1/2000-DGAD dated 9th November 2000, initiated mid-term review (on the basis of request for review by the Automotive Tyre Manufacturers Association and M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai) of anti-dumping duty on imports of SBR of different grades in 1500, 1700 and 1900 series originating in or exported from Japan Korea RP, USA, Taiwan and Turkey as recommended by the Authority vide Final Findings Notification No. 30/1/97 -ADD dated 2/6/1999 and considered it appropriate to continue the anti-dumping duty on SBR 1900 series vide Final Findings (review) notification No. 34/1/2000-DGAD dated 3rd July 2001. The Designated Authority now considers that the sunset review of the anti-dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9(A) of the Customs Tariff Act, 1995. The domestic industry has filed a petition requesting for the continuance of the anti-dumping duty on SBR originating in or exported from Japan, Korea RP and USA for a further period of five years.

3. Procedure:- Having decided to review the final findings of the mid-term review investigations notified vide notification No. 34/1/2000-DGAD dated 3rd July 2001, the Designated Authority hereby initiates sunset review investigations to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty on imports of SBR originating in or exported from Japan, Korea RP and USA in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

4. The review covers all aspects of Final Findings (review) notification no. 34/1/2000-DGAD dated 3rd July 2001.

5. Period of Investigation : The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2002 to 31st March 2003 (12 months).

6. M/s Apar Industries Ltd. Apar House, Corporate Park, Sion-Trombay Road, Chembur, Mumbai- 400 071 and M/s Apcotex Lattices were considered the Domestic Industry in the earlier notification. The Authority proposes to consider these companies as the domestic industry in accordance with the Rules supra.

7. Submission of Information: The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to:-

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties, Udyog Bhavan,
New-Delhi -110011.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. **Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this review notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately. The Designated Authority, in no circumstances, will grant extension of time for response to interested parties. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

10. **Initiation of Anti-Dumping Investigation:** In view of the foregoing paragraph, the Designated Authority initiates anti-dumping (sunset review) investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

11. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within the stipulated period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

2171/11/03-2